

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 11, 1997 (पौष 21, 1918)
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 11, 1997 (PAUSA 21, 1918)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	पृष्ठ 49	भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्रतिकृत पॉट (ऐसे पॉटों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	19		
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं		भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	37	भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, निबंधक और महालेखा परोक्षक, संघ लोक सेवा आयोग रेल विभाग और भारत सरकार में संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	17
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	69
भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं।	31
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सारांश स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि शामिल हैं)	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	5
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के प्रांकड़ों को बताने वाला अनुपूरक	

CONTENTS

	PAGE		PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	49	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	19	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	17
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	37	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	69
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations		PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations		PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	31
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills		PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	5
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc., born in East and High	
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).			

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतर न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों को संबंधित अधिमूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

पर्यावरण और वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 दिसम्बर 1996

संकल्प

विषय :—रांची में पर्यावरण और वन मंत्रालय के नए क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना ।

सं० 7-1/96 क्षेत्रीय कार्यालय (मुख्यालय)—भारत सरकार ने दिनांक 7-1-86 के संकल्प सं० 37-3/85-एफ० पी० के तहत वन संरक्षण मामलों और देश में परियोजनाओं तथा गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रबंधन और प्रदूषण के नियंत्रण के सभी पहलुओं में संबंधित बढ़ते हुए कार्य को निपटाने के लिए दंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, लखनऊ और शिलांग में पांच क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की थी जिनका मुख्यालय नई दिल्ली था। इन क्षेत्रीय कार्यालयों को दिनांक 12-5-88 के संकल्प सं० 17-3/88-पी० सी० के तहत आगे सुदृढ़ किया गया और चंडीगढ़ में छठा क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया।

2. बिहार में वन क्षेत्र के विस्तार और पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यभार के वितरण को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय कार्यालय (पूर्वी क्षेत्र) भुवनेश्वर और क्षेत्रीय (दक्षिण जोन, बंगलौर से बिना कोई अतिरिक्त स्टाफ सृजन के रांची में पूर्वी पठार या अपर ईस्ट) में सातवां क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का निर्णय किया गया है। रांची कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय (पूर्वी क्षेत्र) भुवनेश्वर के लिए गए वन संरक्षक (केन्द्रीय) के द्वारा दो क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए गए सहयोगी कर्मचारियों से चलाया जाएगा। वन संरक्षक (केन्द्रीय) क्षेत्रीय कार्यालय (यू० ई०) रांची में विभागाध्यक्ष होगा और धारा 4.1 (iii) को विधानिर्देशों के साथ पढ़ गए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के वितरण के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

3. क्षेत्रीय कार्यालय निम्नलिखित कार्यों को देखेंगे :—

(क) वानिकी संबंधी कार्य :

(i) विशेष रूप से वनों के संरक्षण पर बल देते हुए चल रही सभी वानिकी विकास परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन करना ;

(ii) ऐसे मामलों जिनमें वन भूमि का उपयोग किया जाना हो, पर शीघ्र कार्यवाही करने और उनको निपटाने में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबन्धों के अन्तर्गत गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए उन प्रस्तावों को तैयार करने में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सहायता करना ;

(iii) जिन मामलों में 40 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र का उपयोग शामिल है, उन स्थानों का मौके पर निरीक्षण आरंभ करना ;

(iv) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अनुमोदित उपयोगों के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों और सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करना ;

(v) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्ग-दर्शी सिद्धांतों के तहत राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के नियंत्रण में वनों के कार्याकरण के लिए प्रबन्ध योजनाओं को तैयार करने में उनकी सहायता करना ;

(vi) वनों और वानिकी गतिविधियों के सभी पहलुओं के आंकड़ों को एकत्र करना उनका मिलान करना भंडारण और पूर्णप्रापण की पद्धति को सरल और कारगर बनाने में राज्यों तथा केन्द्र-शासित प्रदेशों की सहायता करना और ऐसे आंकड़ों को केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय आंकड़ा संसाधन (प्रो-सेसिंग) केन्द्र को भेजना।

(vii) 5 हेक्टेयर की सीमा तक वन भूमि के उपयोग को मंजूरी देना (खनन एवं कच्चा की गई भूमि के नियमितिकरण को छोड़ कर) और 5 हेक्टेयर से लेकर 20 हेक्टेयर तक के मामलों पर राज्य सलाहकार समितियों की सलाह कार्रवाई करना ;

(viii) राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना तैयार करने में सहायता प्रदान करना।

(ix) पर्यावरण वाहिनियों (प्राथमिक अवस्था में पर्यावरण वाहिनियां शुरू करने के लिए 100 जिले

चूने गए) को पर्यवेक्षक और तकनीकी सलाहकार के रूप में सहायता देना :

- (x) जैव-विविधता पर क्षेत्रीय स्तरीय तकनीकी और वैज्ञानिक परामर्श, और
- (xi) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की निगरानी करना ।
- (ख) पर्यावरण प्रबंधन एवं प्रदूषण नियंत्रण कार्य
- (i) पर्यावरणीय स्वीकृति देते समय परियोजनाओं गतिविधियों के लिए निर्धारित शर्तों और सुरक्षा उपायों का क्रियान्वयन करना :
- (ii) उद्योगों, स्थानीय निकायों (राज्य/केन्द्र), सरकारी उपक्रमों आदि द्वारा किए गए प्रदूषण नियंत्रण उपायों को अपनाना ;
- (iii) परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, प्रदूषण नियंत्रण उपाय प्रणालीविज्ञान एवं स्थिति, कानूनी एवं प्रवर्तन उपाय, विशेष संरक्षित क्षेत्रों जैसे कि नलशामियां, कच्छ वनस्पति और जीवमंडल रिजर्वों की पर्यावरणीय सुरक्षा में संबंधित सुचना एकत्र करना व प्रस्तुत करना ।
- (iv) पर्यावरण में संबंधित कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते में लगी हुई संबंधित राज्य सरकारों, केन्द्र सरकारों परियोजनाओं (भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण भारतीय वन सर्वेक्षण तथा भारतीय प्राणि सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालयों सहित), परियोजना प्राधिकारियों केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ सम्पर्क बनाए रखना और संयोजन प्रदान करना ।
- (v) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य पर्यावरण विभागों को परिसंकटमय प्रबन्धन नियमों और लोक वायुवा अधिनियम के अनुप्रयोग से परिचित कराने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना ।

(ग) सामान्य कार्य

समय समय पर इस प्रकार के अन्य कार्य भी संपे जा सकते हैं ।

3. क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्यालय और उनके कार्य क्षेत्र इस प्रकार होंगे —

क्षेत्र	मुख्यालय की स्थिति	कार्यक्षेत्र
1	2	3
(i) पूर्वोत्तर	शिलांग	अरुणाचल प्रदेश असम, मणिपुर, त्रिपुरा मेघालय, मिजोरम और नागालैंड ।

1	2	3
(ii) पूर्व	भुवनेश्वर	उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार ।
(iii) उत्तर	चंडीगढ़	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, पंजाब, केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ व दिल्ली ।
(iv) दक्षिण	बंगलौर	गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, केन्द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पाण्डिचेरी ।
(v) मध्य	लखनऊ	राजस्थान और उत्तर प्रदेश ।
(vi) पश्चिम	भोपाल	गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केन्द्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव ।
(vii) पूर्वी पठार या अपर पूर्व	रांची	बिहार, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम

5. सभी क्षेत्रीय कार्यालय पूर्णतः सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग के नियंत्रण में कार्य करेंगे ।

6. क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या अनुबंध में दर्शायी गई है । विभाग के आदेश से प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के वर्गिततम अधिकारी को विशेष रूप से उस कार्यालय के प्रधान के रूप में पदनामित किया जायेगा और इस प्रकार कार्य करेगा ।

7. यह आदेश इस विषय पर इससे पहले जारी किए गए सभी आदेशों का स्थान लेगा ।

8. यह आदेश तत्काल लागू होगा ।

टी० के० ए० नायर
सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

एम० सी० एस० टी० एम० सेल

नई दिल्ली, दिनांक 11 अक्टूबर 1996

संकल्प

विषय :—अल्पसंख्यक शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मानिट्रिंग समिति का गठन

मं० एफ०-8-1/93-एम० सी०/एस० टी० (एम०)—
इस मंत्रालय के दिनांक 28 जुलाई, 1995 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार ने डा० गिरिजा व्यास संसद सदस्य (लोक सभा) के स्थान पर श्री एम० ए० फातमी, संसद सदस्य (लोक सभा) को अल्पसंख्यक शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मानिट्रिंग समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत करने का निर्णय किया है। इस संशोधन के बाद समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :

- | | |
|--|---------|
| 1. मानव संसाधन विकास मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. श्री ई० टी० मोहम्मद वणीर
शिक्षा मंत्री,
केरल सरकार | सदस्य |
| 3. श्री एम० ए० फातमी,
संसद सदस्य (लोक सभा) | सदस्य |
| 4. श्री के० एम० खान,
संसद सदस्य (राज्य सभा) | सदस्य |
| 5. डा० राज बहादुर शौ०,
1-8-99, सूर्य नगर,
हैदराबाद-500020। | सदस्य |
| 6. श्री इमाम उल हक
अध्यक्ष,
राजस्थान उर्दू अकादमी,
ए-3, मुभाग नगर,
जयपुर। | सदस्य |
| 7. डा० खलिक अंजुम,
सचिव,
अंजुमन तरक्की-उर्दू-ए-हिन्द, | सदस्य |
| 8. श्री अनिल बांदिया,
अध्यक्ष,
लोक जु'विण परिषद,
डी-ब्लॉक, 10-बी,
क्षालना इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र,
जयपुर। | सदस्य |

9. सदस्य-सचिव,
अल्पसंख्यक आयोग

सदस्य

10. कुक्षपति,
जामिया मिलिया इस्लामिया,
नई दिल्ली।

सदस्य

11. सचिव (स्कूल शिक्षा),
बिहार सरकार,
पटना।

सदस्य

12. सचिव (कूस्म शिक्षा),
मान्य प्रदेश सरकार,
हैदराबाद।

सदस्य

13. सचिव (स्कूल शिक्षा),
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ।

सदस्य

14. सचिव (स्कूल शिक्षा),
जम्मू और कश्मीर सरकार,
जम्मू तवी थीनगर।

सदस्य

15. संयुक्त सचिव,
शिक्षा विभाग,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

सदस्य-सचिव

2. समिति द्वारा किया जाने वाला कार्य :

"कार्य योजना, 1992 के अनुसूची-3—अल्पसंख्यक शिक्षा के कार्यान्वयन की निगरानी करना"

3. पदेन सदस्यों से भिन्न समिति के सदस्यों का कार्य-काल सीमा वर्ष का होगा। कार्यकाल दिनांक 28 जुलाई, 1995 के संकल्प के जारी होने की तारीख से शुरू होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण के सुचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अपक सदस्य,
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 24th December, 1996

RESOLUTION

Sub : Establishment of a new Regional Office of the Ministry of Environment & Forests at Ranchi.

No. 7-1/96-RO(HQ).—The Government of India had set up five Regional Offices of the Ministry of Environment & Forests (MOEF) vide Resolution No. 37-3/85-FP dt. 7-4-86 at Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Lucknow and Shillong with a Headquarter Unit at New Delhi to deal with Forest Conservation matters and the increasing work relating to all aspect of Environmental Management and Pollution Control of projects and activities in the country. The Regional offices were further strengthened vide Resolution No. 17-3/88-PC dt. 12-5-88 of the Regional Offices and opening the sixth Regional Office at Chandigarh.

2. Keeping in view the extent of forest areas in Bihar and the distribution of work load amongst the Eastern Regional Offices it has been decided to set up the seventh Regional Office at Ranchi Eastern plateau or Upper-East (UE) carving it out from RO (EZ) Bhubaneswar and RO (SZ) Bangalore without creating additional staff. Ranchi Office will be manned by a Conservator of Forests (C) drawn from RO (EZ) Bhubaneswar with supporting staff drawn from the two Regional Offices. The Conservator of Forests (C) in RO (UE) Ranchi will be the Head of the Department and also exercise powers delegated for diversion of forest land under Forest (Conservation) Act, 1980 read with guide lines section 4.1.(iii).

3. The Regional Offices will discharge the following functions:—

A. FORESTRY FUNCTIONS

- (i) To monitor and evaluate all ongoing forestry development projects and schemes with specific emphasis on conservation of forests;
- (ii) To assist the States and Union Territories in preparation of proposals involving diversion of forest lands for non-forestry purposes under the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980 for expeditious processing and disposal of such cases;
- (iii) To undertake physical inspection of sites in cases of diversion of forests involving an area of more than 40 ha;
- (iv) To monitor the implementation of conditions and safeguard stipulated by the Central Government in regard to diversions approved under the Forests (Conservation) Act, 1980;
- (v) To assist the States and Union Territories in the preparation of management plans for working of forests under their control within the framework of guidelines issued by the Central Government from time to time;
- (vi) To assist the States and Union Territories in streamlining collection, collation, storage and retrieval of data covering all the facets of forests and forestry activities and to transmit such data to the Central Government/Central Data Processing Centre;
- (vii) Approval of diversion of forest land to the extent of 5 ha. (except mining and regularisation of encroachment) and to process cases between 5 ha. to 20 ha. in consultation with the State Advisory Committees;
- (viii) Rendering assistance in preparation of the National Forestry Action Plan (NFAP)

(ix) To assist Paryavaran Vahinis (Total 100 District have been selected for starting Paryavaran Vahinis in the initial stage) as observers and technical advisors;

(x) Regional level technical & Scientific consultation on biological diversity; and

(xi) Monitoring of Centrally Sponsored schemes.

B. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND POLLUTION CONTROL FUNCTIONS

- (i) To followup implementation of conditions and safeguards laid down for projects/activities when environmental clearance is given;
- (ii) To follow up pollution control measures taken by industries, local bodies, Government (State/Centre) undertakings etc.
- (iii) To collect and furnish information relating to environmental impact assesment of projects, Pollution control measures, methodology and status, legal and enforcement measures, environmental protection for special conservation areas like wetlands, mangroves and biosphere reserves;
- (iv) To maintain liaison and provide linkage with the concerned State Governments, with Central Government Agencies, (including Regional Offices of BSF, FSI & ZSI) with Project Authorities, with the Regional Offices of the Central Pollution Control Board; with State Pollution Control Boards and with Non-Government Organisation involved in implementation of programmes relating to environment; and
- (v) To organize work-shops for State Pollution Control Board and State Environment Departments to acquaint with the application of Hazardous Management Rules and Public Liability Act.

C. GENERAL FUNCTIONS

Such other work may be assigned from time to time.

3. The Headquarters of the Regional Offices and their jurisdictions would be as follows:

Region	Location of Headquarter	Jurisdiction
1	2	3
(i) North East	Shillong	Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Tripura, Meghalaya Mizoram & Nagaland.
(ii) East	Bhubaneswar	Orissa, Andhra Pradesh, UTs, Andaman & Nicobar.
(iii) North	Chandigarh	Haryana, H.P., J & K, Punjab, UTs of Chandigarh and Delhi.
(iv) South	Bangalore	Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, UTs Lakshadweep & Pondicherry.
(v) Central	Lucknow	Rajasthan & U.P.
(vi) West	Bhopal	Gujarat, Maharashtra, Madhya

1	2	3
		Pradesh and UTs of Dadra, Nagar & Haveli, Daman & Diu.
(vii) Eastern Plateau or Upper East	Ranchi	Bihar, West Bengal, Sikkim.

5. All Regional Offices will function under the over all control of the Ministry.

6. The complement of staff sanctioned for the Regional Offices is shown in the Annexure. The Senior most officer at each Regional Office will be specifically designated by an order of the Ministry as Head of the Office and will function in that capacity.

7. This order supersedes all previous orders on the subject.

8. This order will come into force with immediate effect.

T. K. A. NAIR
Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF EDUCATION)

SC/ST(M) CELL

New Delhi, the 11th October 1996

RESOLUTION

Sub : Constitution of National Monitoring Committee on Minorities Education.

No. F. 8-1/93-SC/ST(M)—In partial modification of this Ministry's Resolution of even number dated 28th July, 1995, Government of India have decided to nominate Shri M.A. Fatmi, Member of Parliament (Lok Sabha) in place of Dr. Girija Vyas, Member of Parliament (Lok Sabha) as a Member of National Monitoring Committee on Minorities Education. After this modification, the composition of the Committee is as under:—

(i) Union Minister of Human Resource Development	Chairman
(ii) Shri E.T. Mohammed Basheer Education Minister Government of Kerala	Member
(iii) Shri M.A. Fatmi Member of Parliament (Lok Sabha)	Member
(iv) Shri K.M. Khan Member of Parliament (Rajya Sabha)	Member

(v) Dr. Raj Bahadur Gaur 1-8-1/99, Surya Nagar, Hyderabad-500020.	Member
(vi) Shri Inam-ul-Haque, Chairman, Rajasthan Urdu Academy, A-3, Subhash Nagar, Jaipur.	Member
(vii) Dr. Khalique Anjum Secretary, Anjuman Taraqui-Urdu-E-Hind	Member
(viii) Shri Anil Bordia Chairman, Lok Jumbish Parishad, D-Block, 10B, Jhalana Institutional Area, Jaipur.	Member
(ix) Member-Secretary, Minorities Commission	Member
(x) Vice-Chancellor, Jamia Millia Islamia, New Delhi.	Member
(xi) Secretary (School Education), Government of Bihar Patna.	Member
(xii) Secretary (School Education), Government of Andhra Pradesh Hyderabad.	Member
(xiii) Secretary (School Education), Government of Uttar Pradesh, Lucknow.	Member
(xiv) Secretary (School Education), Government of Jammu & Kashmir, Jammu Tawi/Srinagar.	Member
(xv) Joint Secretary, Department of Education, Government of India, New Delhi	Member-Secretary

- The terms of reference of the Committee is
"To monitor the implementation of Chapter 3-Minorities' Education of the Programme of Action 1992."
- The tenure of office of the Members of the Committee other than ex-officio members, shall be three years. The tenure shall take effect from the date of issue of the Resolution dated 28th July, 1996.

ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to the Chairman and other members of the Committee.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

CHAMPAK CHATTERJEE
Joint Secy.

